हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 05 जुलाई 2025, समय 1305 (5 मिनट)

केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-एनपीएस के अन्तर्गत वर्तमान में उपलब्ध सभी कर लाभ नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना-यूपीएस में भी लागू रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीएस को कर ढांचे के अन्तर्गत शामिल करना पारदर्शी, सुगम और कर-कुशल विकल्पों के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करने के सरकार के प्रयास में एक और कदम है।

****

हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डा. कृष्ण लाल मिड्ढा ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि अपने-अपने नगरों को “स्मार्ट" ही नहीं, बल्कि समर्थ, समावेशी और सतत बनाएं ताकि 'विकसित भारत' का सपना केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जमीनी सच्चाई बन सके। वो कल मानेसर में नगर निकाय के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे।उपाध्यक्ष ने कहा कि इस सम्मेलन में "संवैधानिक लोकतंत्र की मजबूती और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका" जैसे विषय पर गहन चर्चा न केवल सामयिक है, बल्कि भारत को 'विकसित राष्ट्र' बनाने की दिशा में भी अत्यंत प्रासंगिक है।उन्होंने कहा कि नगर निकायों की सशक्तता केवल कागज़ों पर नहीं, ज़मीन पर दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सभी राज्य अपने-अपने नगर निकायों को सशक्त, उत्तरदायी और नागरिकों के लिए जवाब देह बनाएंगे, तभी हम संवैधानिक लोकतंत्र को उसकी पूर्णता में अनुभव कर पाएंगे ।

****

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से पर्यावरण प्रदूषण तो कम होगा ही, साथ ही अच्छे और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता भी होगी।विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि धान की रोपाई लगभग पूरी हो चुकी है और अब फसल में डीएपी और यूरिया खाद की खपत बढ़ेगी। इसलिए अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि खाद की कमी न हो और यूरिया और डीएपी खादों की कालाबाजारी न हो। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे डीएपी और यूरिया खाद का रिकॉर्ड रखें और यह व्यवस्था करें कि हरियाणा की खाद दूसरे राज्यों में न जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई खाद की कालाबाजारी करता है, नकली दवाइयां और बीज बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

****

उद्यान विभाग के प्रमुख डा. अर्जुन सिंह सैनी ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में तीन नए उत्कृष्ट फल केंद्र खोले जाएंगे। रादौर में स्ट्रॉबेरी, नारायणगढ़ में लीची और तीसरा केंद्र हिसार में खोला जाएगा। उद्यान विभाग के उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र लाडवा में योजित 3 दिवसीय 7वें फल मेले में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य किसान की मदनी बढ़ाने के लिए तकनीक के साथ उनकी पैदावार बढ़ाना है। श्री अर्जुन सिंह ने कहा है कि इस सामी प्रदेश में उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र लाडवा सहित 14 ऐसे केंद्र चल रहे हैं, जो अब बढक़र 17 हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिंजौर में सेब मंडी शुरू हो चुकी है और मंडी के दूसरे चरण का

काम चल रहा है। इसके अलावा गन्नौर में 550 एकड़ में फल, फूल व सब्जी मंडी का निर्माण किया जा रहा है।इस दौरान महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति एसके मल्होत्रा, लाडवा फल केन्द्र के उपनिदेशक डा. राकेश कुमार, भी मौजूद रहे।

****

हरियाणा में अगली जनगणना वर्ष 2027 में की जाएगी। जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 निर्धारित की गई है।हरियाणा सरकार ने अधिसूचित किया है कि राजस्व एवं पदा प्रबंधन तथा चकबंदी विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त युक्त डॉ. सुमिता मिश्रा जनगणना 2027 से संबंधित सभी गतिविधियों की देखरेख के लिए नोडल अधिकारी होंगी। वे राज्य सरकार, जनगणना विभाग और भारत सरकार के विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी तालमेल सुनिश्चित करेंगी।

****

केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दिए जाने वाले वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन व सिफारिश करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई को समाप्त हो रही है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन व सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त किए जा रहे हैं।एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन पुरस्कारों में नामतः पद्म विभूषण, पद्म भूषण व पद्म श्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित, इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत 'उत्कृष्ट कार्य' के लिए सम्मानित किया जाता है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरी, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग दि जैसे सभी क्षेत्रों अथवा विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों व सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्य सरकारी सेवक, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी, पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं हैं।

****